परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 10 अप्रैल, 2017 पर आधारित है।

ASIAN DEVELOPMENT BANK

एशियाई विकास बैंक

भारत: मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना

परियोजना का नाम	मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना
परियोजना की संख्या	48493-002
देश	भारत
परियोजना की स्थिति	प्रस्तावित
परियोजना प्रकार/ सहायता की विधि	ऋण
निधीयन का स्रोत/राशि	**ऋण: मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना** साधारण पूंजी संसाधन — यूएस डॉलर 150.00 मिलियन
रणनीतिक कार्यसूची	समावेशी आर्थिक विकास
परिवर्तन के प्रेरक	अभिशासन और क्षमता विकास

सेक्टर/उप–सेक्टर	**शिक्षा** - तकनीकी तथा व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण
लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण	प्रभावी लैंगिक मुख्यधारीकरण
विवरण	एशियाई विकास बैंक के प्रस्तावित ऋण से राज्य की तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली को आधुनिक बनाने और उसमें सुधार करने के मध्य प्रदेश शासन के प्रयासों को बल मिलेगा ताकि यहां के कार्यबल को बढ़ते हुए द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों के लिए अपेक्षित कौशल से सुसज्जित किया जा सके।
परियोजना तर्काधार और देश/क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबंध	मध्य भारत में स्थित मध्य प्रदेश आबादी (72.6 मिलियन) के हिसाब से देश का छठा सबसे बड़ा राज्य है। गत दशक में सरकार के संगठित प्रयासों के फलस्वरुप राज्य की भौतिक अवस्थानाओ सड़कों, बिजली, पानी तथा स्वच्छता में बहुत सुधार हुआ है। 2006 से 2012 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, की तुलना में मध्यप्रदेश में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। समग्र गरीबी का प्रतिशत 2004 से 2005 और 2011 से 2012 के बीच 48.6 प्रतिशत से घटकर 31.6 प्रतिशत रह गया है। राज्य विद्युत, सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमेटिव, वस्त्र, उपभोक्ता सामान, मशीनरी, बैंकिंग तथा वित्त, आतिथ्य सत्कार और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के निवेशों को आकर्षित कर रहा है। एशियाई विकास बैंक के प्रस्तावित ऋण से राज्य की तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली को आधुनिक बनाने और उसमें सुधार करने के मध्य प्रदेश शासन के प्रयासों को बल मिलेगा ताकि यहां के कार्यबल को बढ़ते हुए द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों के लिए अपेक्षित कौशल से सुसज्जित किया जा सके। 2011 में, मध्य प्रदेश की आबादी (42 मिलियन) का 59 प्रतिशत हिस्सा 15 से 59 वर्ष की कार्य आयु समूह में था। अनुमान है कि 2012 से 2022 के बीच मध्य प्रदेश के लगभग 9 मिलियन युवा कार्यबल में शामिल होंगे। तथापि, राज्य में कार्य आयु समूह में प्रवेश करने वाले 15 से 29 वर्ष के लोगों की बेरोजगारी दर 9 प्रतिशत है जो पूरे कार्य आयु समूह की औसत बेरोजगारी दर 3 प्रतिशत से कहीं अधिक है। 2013 तक मध्यप्रदेश के 63 प्रतिशत कार्यबल को प्राथमिक क्षेत्र, 21 प्रतिशत को द्वितीयक क्षेत्र तथा केवल 17 प्रतिशत को तृतीय क्षेत्र में रोजगार प्राप्त था हालांकि राज्य के पहलू सकल घरेलू उत्पाद में उनका हिस्सा क्रम से 26 प्रतिशत, 28 प्रतिशत और 46 प्रतिशत बैठता है। मध्य प्रदेश के आर्थिक तथा रोजगार प्रोफाइल के बीच में यह ढांचागत विसंगति आंशिक है, जो इस तथ्य को इंगित करता है लगभग 90 प्रतिशत कार्यबल के पास औपचारिक तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण की सुविधा नहीं है। 213 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जो मध्य प्रदेश की तकनीकी तथा व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली की रीड की हड्डी हैं, में से अधिकांश 40 वर्ष से अधिक पुराने हैं। अधिकांश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पुराने पाठ्यक्रमों और उपकरणों, संकाय सदस्यों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण की कमी, अपर्याप्त औद्योगिक इंगेजमेंट तथा कमजोर परामर्शी और प्लेसमेंट सेवा के चलते क्षमता से नीचे कार्य निष्पादन कर रहे हैं। अतः मध्य प्रदेश सरकार तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण सुधार पर बल दे रही है ताकि अपने युवाओं को अपेक्षित कौशल प्रदान कर सकें और वे प्राथमिक से द्वितीय और तृतीय श्रेणी के जॉब्स में जा सके। एडीबी के ऋण से डीटीईएसडी को अर्थव्यवस्था की बदलती हुई जरूरतों के अनुसार राज्य के आईटीआई नेटवर्क को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। राजधानी भोपाल में एक ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जाएगा ताकि कुशल कामगार अंतरराष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकें और विदेशी नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकें। चुनिंदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों

	का व्यापक स्तर पर सुधार किया जाएगा ताकि वह वृद्धि क्षेत्रों में उच्च प्रशिक्षण प्राप्त प्रदान कर सके। यह परियोजना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के दायरे को राज्य के पिछड़े क्षेत्रों तक ले कर जाएगी और महिलाओं, विकलांगों तथा अन्य कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसकी वजह से अन्य विभागों द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ समन्वय सुनिश्चित करते हुए तथा सभी प्रशिक्षण प्रशिक्षणों को भारत के राष्ट्रीय कौशल शिक्षा फ्रेमवर्क के साथ जोड़ते हुए राज्य कौशल विकास मिशन के जनादेश को सफल बनाने में मध्य प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण परिषद की क्षमता का विकास होगा। प्रस्तावित प्रयोजना से इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी, 2013–2017 की प्राथमिकताएं परिलक्षित होंगी, जिनका उद्देश्य समावेशी विकास की ओर भारत के प्रयासों को बल प्रदान करना है। भारत की कौशल विकास तथा उद्यमशीलता, 2015 संबंधी राष्ट्रीय नीति के अंग के रूप में भारत सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक्स के आधुनिकीकरण और विस्तार, से निजी क्षेत्र द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार करने की प्राथमिकताएं तय की हैं ताकि 2022 तक 300 मिलियन लोगों को कौशल प्रदान किया जा सके। यह परियोजना स्ट्रेटजी 2020 की मध्यावधि समीक्षा से जुड़ी है जिसमें मानव पूंजी विकास को प्रोत्साहन देने और सरकारी निजी भागीदारी को सहायता देने के लिए एडीबी को बुनियादी शिक्षा के उपरांत तथा तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पर फोकस करने पर बल दिया गया है।
प्रभाव	मध्यप्रदेश में बाजार प्रासंगिक तकनीकी और व्यवसायिक कौशल युक्त अधिक उत्पादक कार्यबल का सृजन हुआ
परिणाम	परियोजना के प्रशिक्षुओं रोजगार क्षमता में वृद्धि हुई
आउटपुट्स	औद्योगिक अपेक्षाओं के अनुरूप मध्य प्रदेश तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रणाली को आधुनिक बनाया गया बाजार से जुड़ा कौशल इकोसिस्टम सृजित हुआ कमजोर वर्गों को तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण में इक्विटी में वृद्धि हुई तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रबंधन की क्षमता में सुधार हुआ
भौगोलिक अवस्थिति	
संरक्षा संवर्ग	
पर्यावरण	ख
अस्वैच्छिक पुनर्वास	ग

स्वदेशी लोग ग

पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश

पर्यावरण पहलू

अस्वैच्छिक पुनर्वास

स्वदेशी लोग

स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान

परियोजना कार्यान्वयन के दौरान

जिम्मेदार स्टाफ

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	ली, सुनहवा
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	मानव तथा सामाजिक विकास प्रभाग, एसएआरडी
निष्पादक अभिकरण	**तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विकास विभाग, मध्य प्रदेश सरकार** चौथी मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल, 462004

समयसारणी

अवधारणा मंजूरी	01 दिसंबर 2016
तथ्य अन्वेषण	17 जुलाई 2017 से 21 जुलाई 2017 तक
एमआरएम	15 सितंबर 2017
अनुमोदन	-
अंतिम पुनरीक्षा मिशन	-
अंतिम पीडीएस अद्यतन	22 मार्च 2017

परियोजना डेटा शीट्स (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम पर संक्षिप्त जानकारी दी गई हैः क्योंकि पीडीएस प्रगति–में–कार्य होता है, इसके आरंभिक पाठ में कुछ जानकारी सम्मिलित नहीं होना संभव है, परंतु यह उपलब्ध होते ही जोड़ दी जाएगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में जानकारी अनंतिम एवं संकेतात्मक है।

एशियाई विकास बैंक इस परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में दी गई जानकारी इसके उपयोगकर्त्ताओं के लिए, किसी भी प्रकार के आश्वासन रहित संसाधन मात्र के रूप में उपलब्ध कराता है। यद्यपि एशियाई विकास बैंक उच्च गुणवत्ता की विषयवस्तु उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, तदपि जानकारी विपण्यता, विशेष प्रयोजन हेतु उपयुक्तता और अनतिक्रमण की सीमांकन वारंटियों सहित किसी भी प्रकार की वारंटी, अभिव्यक्त अथवा अभिप्रेत, के बिना "जैसी है" आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। एशियाई विकास बैंक ऐसी जानकारी की सटीकता अथवा पूर्णता के संबंध में विनिर्दिष्ट रूप से कोई वारंटी अथवा अभिवेदन प्रस्तुत नहीं करता है।